

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 22 से 28 अगस्त 2026

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 14

अंक-105

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

प्रधानमंत्री मोदी के 'शक्ति की सप्तधारा' विजन को साकार करने का संकल्प: शिवराज सिंह चौहान

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, तकनीक और वैश्विक बाजार पर जोर, विकसित भारत का लक्ष्य

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित 'शक्ति की सप्तधारा' को साकार करने में पूरा कृषि और ग्रामीण विकास परिवार जुट जाएगा। पूसा परिसर में आयोजित संकल्प कार्यक्रम में मंत्री ने अधिकारियों, किसानों, लखपति दीदियों, निर्यातकों और फूड प्रोसेसर्स के साथ मिलकर विकसित भारत के विजन पर चर्चा की।

चौहान ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इस विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि भारतीय किसानों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत जगह बना सकें। उन्होंने हर राज्य और जिले के लिए अलग कृषि रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता, तकनीक और एआई का उपयोग, वैल्यू एडिशन तथा ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य भी दोहराया गया।

इससे उर्वरक कंपनियां जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और राष्ट्रीय उर्वरक; कृषि रसायन क्षेत्र की यूपीएल; ट्रैक्टर और कृषि उपकरण कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा एस्कॉर्ट्स कुबोटा; और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयर भी सकारात्मक रह सकते हैं।



मध्य प्रदेश ने भव्य योजना के तहत 11 औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव रखा

₹8,144 करोड़ की लागत, 9,000 एकड़ से अधिक भूमि पर प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य-BHAVYA) के तहत 11 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पेश किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में NICDIT की बैठक में यह प्रस्ताव रखा।

इन पार्कों का कुल क्षेत्रफल 9,047 एकड़ से अधिक है और अनुमानित लागत ₹8,144.35 करोड़ है। इन्हें प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा, ताकि उद्योग आसानी से स्थापित हो सकें। प्रस्तावित स्थानों में उज्जैन का अवंतिका इंडस्ट्रियल सेंटर, धार का भेंसोला (टेक्सटाइल पार्क), देवास-शाजापुर, रतलाम, सीहोर, सागर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी और रीवा शामिल हैं।

ये पार्क फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आईटी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए डे-केयर और हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं।

भव्य योजना के तहत देशभर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश इन प्रस्तावों के जरिए पहले चरण में अधिकतम मंजूरी हासिल करना चाहता है।

इससे औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट (अल्ट्राटेक, अम्बानी), स्टील (जिंदल स्टील, टाटा स्टील), पावर और इंजीनियरिंग कंपनियों (एलएंडटी, बीएचईएल) को लाभ मिल सकता है। टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर की कंपनियां भी सकारात्मक रह सकती हैं।

इंतजार महंगा पड़ सकता है

5 साल की देरी =
करोड़ों का नुकसान



आज
शुरू किया निवेश

₹10,000/महीना SIP

12% रिटर्न X 30 साल

कुल वेल्थ

₹3.53 करोड़

आपका निवेश = ₹36 लाख

शुरू किया निवेश
5 साल बाद

₹10,000/महीना SIP

12% रिटर्न X 25 साल

कुल वेल्थ

₹1.90 करोड़

आपका निवेश = ₹30 लाख



देरी की कीमत : ₹1.63 करोड़

5 साल की देरी ने आपके ₹6 लाख बचाए, लेकिन ₹1.63 करोड़ की वेल्थ कम कर दी।

आज की छोटी SIP, कल की बड़ी वेल्थ।

* सभी आंकड़े अनुमानित हैं और केवल उदाहरण के लिए हैं।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025

visionadvisorymkt@gmail.com



Cabinet Clears ₹13,041 Crore Rail and Road Projects

Howrah-Chennai Route to Get Full Four-Line Corridor; Major Boost to Freight and Connectivity

New Delhi: The Union Cabinet has approved five infrastructure projects worth ₹13,041 crore, including four key railway capacity expansion works and one highway project in Bihar. The biggest highlight is the quadrupling of critical sections on the Howrah-Chennai high-density route.

Three railway projects will create a continuous four-line corridor on the Howrah-Chennai network. These include the 173-km Kharagpur-Bhadrak fourth line (₹3,352 crore), 75-km Bhadrak-Haridaspur fourth line (₹1,583 crore) and 90-km Gummidipundi-Gudur third and fourth lines (₹2,229 crore). Another project

involves third and fourth lines on the 72-km Cuttack-Paradeep section (₹2,286 crore).

Together, the rail projects will add substantial freight capacity, reduce logistics costs by hundreds of crores annually, generate significant employment and cut carbon emissions. They will improve connectivity to major ports such as Paradip, Dhamra and Krishnapatnam, as well as steel and industrial hubs.

The Cabinet also cleared an 83-km four-lane highway from Muzaffarpur to Sonbarsa in Bihar (₹3,591 crore), which will cut travel time and boost links to the

Nepal border.

Stocks Likely to Benefit Railway construction and EPC companies such as IRCON International, RVNL, Rail Vikas Nigam and Larsen & Toubro are expected to gain from execution contracts. Steel producers and port-related stocks may also see positive impact from improved freight movement.

कमजोर मानसून से बढ़ी खाद्य महंगाई, लेकिन ग्रामीण मांग मजबूत: नोमुरा बारिश में 13% की कमी, फिर भी ट्रू-व्हीलर और ट्रैक्टर बिक्री दो अंकों में बढ़ी

नई दिल्ली: नोमुरा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 13 प्रतिशत कमजोर चल रहा है, जिससे खाद्य महंगाई पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि ग्रामीण मांग अभी तक लचीली बनी हुई है।

जून से मध्य अगस्त तक कुल वर्षा सामान्य से 13 प्रतिशत कम रही है। दक्षिणी क्षेत्र में 21 प्रतिशत और पूर्व-उत्तर पूर्व में 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जून में बारिश 39 प्रतिशत कम रही थी, जबकि जुलाई में थोड़ी रिकवरी हुई। जलाशय स्तर भी पिछले साल की तुलना में काफी नीचे है।

खरीफ बुवाई करीब 2 प्रतिशत कम हुई है। चावल की बुवाई में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। अप्रैल से मध्य अगस्त के बीच खाद्य

कीमतों में 5.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में हुई 1.9 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक है। चावल और चीनी की कीमतों में खास तेजी देखी गई।

इसके बावजूद जुलाई में ट्रू-व्हीलर और ट्रैक्टर की बिक्री दो अंकों में बढ़ी है, जो ग्रामीण मांग की मजबूती का संकेत है। हालांकि ग्रामीण मजदूरी वृद्धि में नरमी और किसानों की व्यापार शर्तों में दबाव दिख रहा है।

नोमुरा का कहना है कि मानसून की कमी का असर अभी खाद्य महंगाई पर ज्यादा और मांग पर अपेक्षाकृत कम पड़ा है। एल नीनो के मजबूत होने की आशंका से रबी सीजन पर भी नजर रखनी होगी।



Govt Approves Incentive Scheme to Boost Domestic PNG Connections

CGD Companies to Get Extra Cheap APM Gas for Every New Connection; Faster Clean Energy Push

Mumbai: The government has approved a new incentive scheme to accelerate the expansion of domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across the country. The move aims to bring clean, safe and affordable cooking fuel to more households while reducing dependence on imported LPG.

Under the scheme, eligible City Gas Distribution (CGD) companies will receive an additional 200 Standard Cubic Metres (SCM) of cheap domestically produced APM gas for every extra domestic PNG connection that is built and activated. Currently, India has around 1.74 crore

domestic PNG connections, many of which remain inactive. The scheme will be implemented in two phases of six months each, starting from 1 September 2026. It is expected to significantly shorten the payback period for new connections from about 10 years to just three years, giving strong financial motivation to CGD players.

An integrated PNG registration portal is also being developed to streamline the process. Officials said the initiative will help expand the PNG network faster, improve volume growth for CGD companies and support India's clean

energy transition.

Major beneficiaries include companies such as Indraprastha Gas, Mahanagar Gas, Gujarat Gas, Adani Total Gas and GAIL. The scheme is likely to strengthen their profitability and expansion plans in the domestic PNG segment.



मध्य प्रदेश में बिजनेस-रेडी डिस्ट्रिक्ट्स वर्कशॉप: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर जोर

भोपाल में डी-बीआरएपी 2025 और बीआरएपी 2026 रोडमैप पर मंथन, निवेशक सुविधा और सहयोगी शासन पर फोकस

भोपाल: मध्य प्रदेश में कारोबार सुगमता को जिला स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भोपाल में महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। “बिल्डिंग बिजनेस-रेडी डिस्ट्रिक्ट्स: मध्य प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार यात्रा और बीआरएपी रोडमैप” विषय पर आयोजित इस वर्कशॉप में राज्य और जिला स्तर पर सुधारों को तेज करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।

कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) द्वारा डेलॉयट ईओडीबी टीम के सहयोग से कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में किया गया। इसमें भोपाल और रायसेन जिले के अधिकारी, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि, बीआरएपी नोडल अधिकारी और उद्योगपति शामिल हुए।

मध्य प्रदेश सरकार जिलों को निवेश के लिए पूरी तरह तैयार बनाने पर जोर दे रही है। डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (डी-बीआरएपी) 2025 और राज्य स्तर के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2026 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर

फोकस रहा। अधिकारियों ने कहा कि अब सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिला स्तर पर सेवाओं की डिलीवरी तेज करनी होगी, मंजूरी का समय घटाना होगा और निवेशकों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना होगा।

प्रथम सत्र में सरकारी विभागों के अधिकारियों को डी-बीआरएपी 2025 के फ्रेमवर्क, आकलन पद्धति, जिलों की भूमिका, साक्ष्य आवश्यकताओं और समय-सीमा के बारे में विस्तार से बताया गया। बीआरएपी 2026 के तहत सुधार श्रेणियों, यूजर-स्पेसिफिक रिफॉर्म और विभागीय तैयारियों पर भी चर्चा हुई। द्वितीय सत्र में उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों को शामिल किया गया, जहां मध्य प्रदेश की ईओडीबी सुधार यात्रा, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल, डिजिटल गवर्नेंस, नियामकीय सुधार और 2026 के ईओडीबी अधिनियम पर प्रकाश डाला गया।

दो महत्वपूर्ण पैनल चर्चाएं हुईं। पहली में बिजनेस-रेडी डिस्ट्रिक्ट्स के तहत जिला प्रशासन की निवेशक सुविधा में भूमिका, अंतर-विभागीय

समन्वय, मंजूरी समय कम करना, शिकायत निवारण और डिजिटल सेवा डिलीवरी पर चर्चा हुई। दूसरी में सहयोगी शासन के अंतर्गत सरकार, उद्योग और निवेशकों के बीच साझेदारी, नियामकीय बाधाएं, निवेशक फीडबैक और भविष्य की सुधार प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई। पैनल में भोपाल और रायसेन के कलेक्टर, एमपीआईडीसी अधिकारी, प्रमुख उद्योगपति, इन्वेस्ट इंडिया प्रतिनिधि तथा सीआईआई, फिक्की जैसे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

वर्कशॉप में नियामकीय सरलीकरण, डी-रेगुलेशन, जन विश्वास पहल, निवेशक सुविधा, डिजिटल गवर्नेंस और कुशल कार्यबल विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। “स्टेकहोल्डर फीडबैक से सार्थक सुधार” की थीम के साथ सरकार उद्योग जगत की बात सुनकर नीतियां और अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास कर रही है। जिला स्तर पर सुधारों को मजबूत करने से निवेश आकर्षित होगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार होगा।

निवेश से ज्यादा जरूरी है सही साथ

— निवेश आसान है, सही दिशा मिलना मुश्किल। —



अकेले निवेश का सफर

- ❌ सही फंड चुनना
- ❌ बाजार पर नजर रखना
- ❌ रिकॉर्ड संभालना
- ❌ पोर्टफोलियो की समीक्षा
- ❌ लक्ष्य तय करना



जब साथ हो एक MFD का

- ✅ सही मार्गदर्शन
- ✅ लक्ष्य आधारित योजना
- ✅ पोर्टफोलियो पर निगरानी
- ✅ निवेश में मदद
- ✅ रिकॉर्ड और टैक्स सहायता



सही मार्गदर्शन निवेश को आसान बना सकता है

अपने पार्टनर से बात करें।

*म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



आपने 10 साल नहीं गंवाए।

आपने ₹1.23 करोड़ गंवाए।

30 साल की उम्र में ₹10,000/माह की SIP, 12% रिटर्न के साथ शुरू की।

उम्र 55 ~ ₹1.70 करोड़।



40 साल की उम्र में ₹10,000/माह की SIP, 12% रिटर्न के साथ शुरू की।

उम्र 55 ~ ₹47 लाख।



₹1.23 करोड़

आइए शुरुआत करें, इससे पहले कि यह अंतर और बढ़ जाए।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



ICICI Prudential Value Fund's 22-Year Wealth Journey: From Rs 10,000 SIP to Rs 2.37 Crore

Consistent value strategy delivers 17% XIRR; fund emerges as India's largest actively managed value equity scheme with over Rs 61,000 crore AUM

Mumbai: ICICI Prudential Value Fund has turned a monthly SIP of Rs 10,000 into Rs 2.37 crore over 22 years. The total amount invested stood at Rs 26.4 lakh, generating an XIRR of 17.04% since inception. A one-time lump-sum investment of Rs 1 lakh made at the fund's launch would have grown to about Rs 46.6 lakh by July 31, 2026, delivering a CAGR of 19.11%. In comparison, the same amount invested in the Nifty 50 TRI would have grown to roughly Rs 20.1 lakh at a CAGR of 14.63%. Over shorter periods, the scheme has continued to outperform. It posted a three-year CAGR of 13.44% and a five-year CAGR of 16.05%, against the Nifty 500 TRI's returns of 12.29% and 11.85% respectively. With assets under management of Rs 61,102 crore, the fund is the largest actively managed value-oriented equity scheme in India and accounts for nearly 28% of the total AUM in the value category.

Launched on August 16, 2004 (earlier known as ICICI Prudential Value Discovery Fund), the scheme seeks long-term capital appreciation by investing in companies trading below their intrinsic value across market capitalisations and sectors. It has navigated multiple market cycles while maintaining a diversified, value-oriented approach. The portfolio currently holds 93.31% in equities, with the highest allocation to financial services (38.10%), followed by healthcare, FMCG, information technology and automobiles.

On a risk-adjusted basis, the fund reported an annualised standard deviation of 12.72%, a Sharpe ratio of 0.63 and a beta of 0.79 relative to its benchmark. Portfolio turnover stood at 0.80 times for the equity portion. The scheme is jointly managed by Sankaran Naren, Dharmesh Kakkad and Masoomi Jhurmarvala.

Sankaran Naren, ED & CIO of ICICI Prudential AMC, noted that value investing works over the long term as stocks often take time to realise their intrinsic value. The fund follows a flexible approach without strict market-cap bias, currently maintaining a large-cap tilt where valuations appear attractive. The fund is suitable for investors seeking long-term wealth creation through a value strategy and who can tolerate equity market volatility.



इन्वेस्को का नया फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड लॉन्च: सेक्टरल इक्विटी में निवेश का मौका

ओपन-एंडेड स्कीम 1 सितंबर तक खुली, न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये – हेल्थकेयर इकोसिस्टम पर फोकस

भोपाल: इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड सेक्टरल इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो फार्मास्यूटिकल, हेल्थकेयर और संबद्ध क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करेगा। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 18 अगस्त 2026 से शुरू होकर 1 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा।

यह स्कीम सिर्फ फार्मा कंपनियों तक सीमित नहीं है। इसमें फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरर्स, अस्पताल, डायग्नोस्टिक कंपनियां, कॉन्टैक्ट डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएमओ), कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (सीआरओ), मेडिकल डिवाइस निर्माता, हेल्थकेयर सर्विस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस और अन्य संबद्ध क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। उद्देश्य लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना है।

फंड का प्रबंधन आदित्य खेमानी, हेड ऑफ इक्विटी और फंड मैनेजर, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड करेंगे। बेंचमार्क बीएसई हेल्थकेयर टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) है। जोखिम स्तर 'वेरी हाई' रखा गया है। एनएफओ के दौरान न्यूनतम एकमुश्त निवेश 1,000 रुपये है और आगे की राशि 1 रुपये के गुणक में लगाई जा सकती है। एसआईपी न्यूनतम 100 रुपये से शुरू की जा सकती है। आवंटन के तीन महीने के भीतर रिडेम्प्शन या स्विच पर 0.50 प्रतिशत एग्जिट लोड लगेगा।

इन्वेस्को के अनुसार, भारत का हेल्थकेयर इकोसिस्टम अनुकूल जनसांख्यिकी, बढ़ती स्वास्थ्य सेवा पहुंच, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में वृद्धि,

वैश्विक फार्मा नेतृत्व और नवाचार आधारित अवसरों से आकार ले रहा है। आदित्य खेमानी ने कहा कि देश स्वास्थ्य सेवा खपत में वृद्धि देख रहा है और वैश्विक फार्मा तथा हेल्थकेयर इनोवेशन हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। डोमेस्टिक फार्मा, अस्पताल, डायग्नोस्टिक्स, सीडीएमओ और उभरते सेगमेंट्स में आकर्षक अवसर हैं।

यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो हेल्थकेयर सेक्टर की दीर्घकालिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और सेक्टरल रिस्क सहन कर सकते हैं। हालांकि, सेक्टरल फंड्स में एकाग्रता जोखिम अधिक होता है और बाजार स्थितियों के अनुसार रिटर्न में उतार-चढ़ाव संभव है। निवेशकों को स्कीम डॉक्यूमेंट अच्छी तरह पढ़कर अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार और नीतिगत समर्थन के बीच यह नया फंड निवेशकों को व्यापक हेल्थकेयर वैल्यू चेन में भागीदारी का मौका देता है।



L&T Clinches Ultra-Mega Offshore Order Worth Over Rs 15,000 Crore from Middle East

Energy Hydrocarbon unit bags EPCIC contract for multiple offshore facilities; fabrication at company's world-class yards

Larsen & Toubro (L&T) has secured a major order valued at more than Rs 15,000 crore for the development of multiple offshore facilities in the Middle East. The company's Energy Hydrocarbon Offshore unit bagged the 'ultra-mega' contract that covers engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) of the offshore facilities.

A significant portion of the fabrication work will be executed at L&T's integrated, world-class manufacturing and fabrication facilities. The order ranks among the most significant offshore developments currently underway in the Middle East and reflects the growing investments being made in the region to meet future energy demand.

T Madhava Das, Whole-time Director, Senior Executive Vice President and Head of the Energy Hydrocarbon Division at Larsen & Toubro, said the scale and

complexity of the project demand deep engineering expertise, integrated project execution capabilities and seamless coordination across multiple workstreams. LTEH Offshore has a strong track record of delivering some of the region's most challenging offshore projects, including fixed platforms, subsea pipelines and structures, brownfield upgrades, deep-water subsea infrastructure and decommissioning programmes across global markets.

The win strengthens L&T's position in the international offshore energy space and adds to its robust order book. It also highlights the company's ability to execute large, complex projects involving advanced engineering and high-quality fabrication. With energy demand continuing to rise in the Middle East, such contracts are expected to remain an important growth driver for Indian engineering and construction majors.

Market participants view the order as a positive development for L&T, reinforcing its credentials in the hydrocarbon sector. The project will utilise the company's extensive fabrication infrastructure and experienced project teams, enable efficient delivery while maintain high safety and quality standards. Overall, the contract underscores L&T's competitive edge in winning high-value international orders and its growing contribution to global energy infrastructure development.



अंबानी का 2.73 लाख करोड़ का अंडरग्राउंड दांव: भारत को ऊर्जा झटकों से बचाएगा?

आंध्र प्रदेश में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव – आयात निर्भरता कम करने और स्वदेशी सिंथेटिक गैस बनाने की दिशा में बड़ा कदम

एलुरु: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन (यूसीजी) कॉम्प्लेक्स विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना में 30 वर्षों में करीब 2.73 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है, जो देश के सबसे बड़े ऊर्जा और औद्योगिक निवेशों में से एक बन सकता है।

रिलायंस ने कोयला मंत्रालय की ई-नीलामी के जरिए चिंतलापुडी और रेचेरला कोयला ब्लॉक हासिल किए हैं। चिंतलापुडी ब्लॉक में करीब 905 मिलियन टन और रेचेरला में 2,226 मिलियन टन कोयला भंडार है। कुल मिलाकर करीब 3.13 बिलियन टन कोयला 500-600 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित है, जहां पारंपरिक खनन मुश्किल और महंगा है।

प्रस्ताव के अनुसार, निवेश तीन चरणों में होगा। अन्वेषण और पायलट चरण (2026 की तीसरी तिमाही से 2027 के अंत तक) में 3,000 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे। सफलता मिलने पर 2028-30 के विकास

चरण में 1.20 लाख करोड़ रुपये और 2030 के बाद उत्पादन चरण में 1.50 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।

यूसीजी तकनीक जमीन के नीचे ही कोयले को सिंथेटिक गैस (सिन्गैस) में बदल देती है। इससे हाइड्रोजन, मेथनॉल, अमोनिया और सिंथेटिक नेचुरल गैस (एसएनजी) बनाई जा सकती है। भारत की ऊर्जा मांग बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा बिजली क्षेत्र में मददगार है, लेकिन उर्वरक, रसायन, रिफाइनिंग और स्टील जैसे उद्योगों के लिए गैस और उससे बने उत्पादों की जरूरत बनी रहेगी। स्वदेशी सिन्गैस से एलएनजी, अमोनिया और मेथनॉल आयात में कमी आ सकती है।

यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, आयात बिल घटाने और औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, सफलता पायलट चरण पर निर्भर करेगी। तकनीक को सुरक्षित, नियंत्रित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य साबित करना जरूरी है। गैस लीकेज, भूजल प्रदूषण और जमीन धंसने जैसे जोखिमों पर ध्यान देना होगा।

यदि पायलट सफल रहा तो यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। रिलायंस का यह दांव देश को वैश्विक ऊर्जा झटकों से बचाने की क्षमता रखता है।



LIC Gets RBI Nod to Raise HDFC Bank Stake to Nearly 10%

Insurer Can Increase Holding from 4.11% to 9.99%; Move Strengthens Institutional Ownership

Mumbai: Life Insurance Corporation of India (LIC) has received approval from the Reserve Bank of India to raise its stake in HDFC Bank from the current 4.11% to up to 9.99% of the bank's paid-up share capital or voting rights.

The approval, disclosed in a regulatory filing by HDFC Bank, is subject to applicable RBI conditions and relevant SEBI regulations. LIC currently holds 4.11% of the bank's total share capital as of mid-August. The nod gives the country's largest insurer the flexibility to increase its investment in India's largest private sector bank over time.

Any further acquisition of shares will have to comply with regulatory and statutory requirements. The approval does not mandate an immediate increase to the maximum limit.

The development underscores LIC's growing role as a major institutional investor in the banking sector. A higher stake would deepen its exposure to one of India's strongest financial institutions and reflect continued confidence in the long-term prospects of the private banking space.



Market participants view the RBI clearance as a positive signal for both LIC and HDFC Bank, highlighting the importance of stable institutional ownership in India's banking system while remaining within the prescribed regulatory framework.

ह्यूंदई कारें सितंबर से महंगी होंगी, कीमतों में 1% तक बढ़ोतरी

कच्चे माल और इनपुट लागत बढ़ने से तीसरी बार कीमतें बढ़ाई, ग्राहकों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली: ह्यूंदई मोटर इंडिया ने सितंबर 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में एक प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने कच्चे माल, कमोडिटी और अन्य इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि के साथ भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को इसका कारण बताया है। यह बढ़ोतरी ग्रैंड आई10 एनआईओएस जैसी एंट्री-लेवल हैचबैक से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी आयनिक 5 तक कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होगी। इन गाड़ियों की मौजूदा कीमतें करीब 5.6 लाख रुपये से 55.7 लाख रुपये के बीच हैं।

ह्यूंदई ने कहा कि कंपनी लागत को नियंत्रित करने और बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार दबाव के कारण आंशिक रूप से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। यह इस साल कंपनी की तीसरी कीमत वृद्धि है। इससे पहले जनवरी और जून में भी कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं।

ऑटो सेक्टर में कई कंपनियां महंगाई और लागत दबाव के कारण कीमतें बढ़ा रही हैं। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने भी इस साल मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। निर्यात में भी दबाव बना हुआ है।

ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि खरीद का फैसला जल्द करें, क्योंकि सितंबर से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। इस बढ़ोतरी से मिड-सेगमेंट और प्रीमियम कारों की खरीद लागत थोड़ी और बढ़ जाएगी।



NeoGeo Raises \$20 Million in Series A to Expand Geospatial Intelligence Platform

SBI's Neev II Fund and Aavishkaar Capital Back Startup for Global Growth and Product Development

Gurugram: Geospatial technology startup NeoGeo has raised \$20 million in a Series A funding round co-led by SBI's Neev II Fund and Aavishkaar Capital. The capital will be used to deepen its product portfolio, invest in research and development, strengthen the team and expand into international markets.

Founded in 2019 by Sreeramam GV and Brahman, NeoGeo provides mapping and location-intelligence solutions to governments and enterprises. Its services cover urban governance, utilities, infrastructure, natural resource management and disaster management.

The company collects data through satellite imagery, LiDAR, drones and ground surveys, and applies AI-driven analytics to create industry-specific platforms.

NeoGeo has completed more than 200 projects, mapped over five lakh square kilometres and manages more than 550 satellite-positioning reference stations. The fresh funds will support its shift from project-based services towards scalable software products and help open offices in the Middle East, Europe and the Americas. Founder and CEO Sreeramam said the investment would enable the company to scale its platform business and build

foundational public infrastructure capabilities. The round underscores growing investor interest in geospatial intelligence as a critical layer for smart cities, infrastructure monitoring and sustainable development.



प्रोसस ने नवी में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया, वैल्यूएशन 1.3 बिलियन डॉलर सचिन बंसल की फिनटेक कंपनी को मिला पहला संस्थागत फंड, आईपीओ की तैयारी तेज

नई दिल्ली: सचिन बंसल की फिनटेक कंपनी नवी ने डच निवेशक प्रोसस से 100 मिलियन डॉलर (करीब 850 करोड़ रुपये) का निवेश जुटाया है। इस निवेश के साथ कंपनी का वैल्यूएशन करीब 1.3 बिलियन डॉलर (लगभग 11,000 करोड़ रुपये) आंका गया है।

यह नवी का पहला संस्थागत पूंजी निवेश है। कंपनी 2018 में फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल द्वारा शुरू की गई थी। इससे पहले बंसल ने खुद ही कंपनी में बड़ा निवेश किया था। लेन-देन प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य नियामकीय मंजूरी के अधीन है।

नवी डिजिटल भुगतान, लेंडिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के लेंडिंग आर्म नवी फिनसर्व का एसेट

अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नवी यूपीआई ऐप देश में चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी ने समेकित स्तर पर मुनाफा कमाया है।

सचिन बंसल ने कहा कि प्रोसस का निवेश कंपनी के भविष्य पर मजबूत भरोसे का संकेत है। प्रोसस के पास टेक्नोलॉजी बिजनेस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का वैश्विक अनुभव है।

यह निवेश कंपनी की आईपीओ योजनाओं को भी गति दे सकता है। नवी पहले भी आईपीओ की तैयारी कर चुकी है। फिनटेक सेक्टर में यह सौदा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



AlgoFET Raises ₹15 Crore from Piper Serica to Scale Autonomous Drone Infrastructure

Bengaluru Deeptech Startup Builds Ground Systems for Continuous Drone Operations

Palo Alto: Deeptech startup AlgoFET has raised ₹15 crore in a Pre-Series A round led by Piper Serica to expand its autonomous ground infrastructure for drones. The funding will support product development, manufacturing capacity and deployments across defence, enterprise and global markets.

Founded in December 2023 by IIT Guwahati alumnus Ankit Mishra, AlgoFET focuses on autonomous docking, charging and battery management systems that allow drones to recover, recharge and relaunch without human intervention. The company has already deployed over 2,000 units and holds an order

pipeline of more than 4,000 units, with an order book of around ₹100 crore.

AlgoFET works with leading drone manufacturers and the Indian Army. The fresh capital will help expand its 12,000 sq ft manufacturing facility, strengthen intellectual property and scale operations in India as well as early markets in the US and Europe.

Founder Ankit Mishra said India has invested heavily in drones but lacks the ground infrastructure needed for continuous autonomous operations. "Every mission still ends when the battery does. AlgoFET exists to close that gap," he noted.

Piper Serica highlighted the growing need for systems that support drones beyond

the aircraft itself as their use expands in both civilian and defence applications. The investment positions AlgoFET to build critical infrastructure for India's emerging drone ecosystem.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24252	24733	24547	24399	24213	24065	23879	23731
BANK NIFTY	57762	58789	58279	58021	57511	57253	56743	56485
SENSEX	77541	79145	78537	78039	77431	76933	76325	75827
FINNIFTY	26261	26798	26560	26411	26173	26024	25786	25637
MIDCAP	14875	15195	15096	14985	14886	14775	14676	14565
ACC	1309	1363	1343	1326	1306	1289	1269	1252
AXISBANK	1246	1305	1281	1263	1239	1221	1197	1179
ABCAPITAL	411	437	425	418	406	399	387	380
BHARTIARTL	1947	2057	2025	1986	1954	1915	1883	1844
BHEL	410	455	445	428	418	401	391	374
BIOCON	413	433	428	420	415	407	402	394
BEL	414	428	422	418	412	408	402	398
CDSL	1388	1496	1449	1418	1371	1340	1293	1262
DATAPATTERN	4807	5587	5292	5050	4755	4513	4218	3976
ESCORTS	3088	3268	3213	3151	3096	3034	2979	2917
EICHERMOTOR	8000	8344	8255	8127	8038	7910	7821	7693
FEDERAL BANK	360	380	372	366	358	352	344	338
GRINFRAPROJECT	875	928	912	893	877	858	842	823
HDFCBANK	729	754	744	736	726	718	708	700
HCLTECH	1306	1420	1391	1349	1320	1278	1249	1207
HINDUNILVR	2016	2127	2101	2059	2033	1991	1965	1923
HAL	4978	5273	5211	5095	5033	4917	4855	4739
HYUNDAI	2217	2350	2300	2259	2209	2168	2118	2077
IOC	136	144	142	139	137	134	132	129
ICICIBANK	1418	1463	1443	1431	1411	1399	1379	1367
INFY	1119	1208	1188	1153	1133	1098	1078	1043
ITC	270	290	284	277	271	264	258	251
KOTAKBNK	403	429	418	410	399	391	380	372
LICHOUSING	498	529	520	509	500	489	480	469
LT	4088	4190	4145	4116	4071	4042	3997	3968
LUPIN	2195	2323	2294	2245	2216	2167	2138	2089
MARUTI	13595	14157	14038	13817	13698	13477	13358	13137
M&M	3417	3543	3500	3458	3415	3373	3330	3288
MGL	1116	1232	1203	1159	1130	1086	1057	1013
MAZGAONDOC	2550	2683	2651	2601	2569	2519	2487	2437
PFC	363	388	382	373	367	358	352	343
RECLTD	326	353	347	337	331	321	315	305
RELIANCE	1314	1360	1345	1329	1314	1298	1283	1267
SBIN	1041	1089	1079	1060	1050	1031	1021	1002
SUNPHARMA	1895	2023	1986	1941	1904	1859	1822	1777
SHRIRAMFINANCE	1130	1189	1165	1147	1123	1105	1081	1063
TITAN	5080	5224	5167	5124	5067	5024	4967	4924
TCS	2295	2454	2408	2351	2305	2248	2202	2145
TATAMOTORS	317	345	340	328	323	311	306	294
UPL	569	594	584	577	567	560	550	543
VALIENT	305	346	334	319	307	292	280	265
WIPRO	180	189	187	183	181	177	175	171

Cipla Completes Merger with Wholly-Owned Subsidiary Inzpera Health Sciences

Aims to Streamline Operations, Cut Costs and Unlock Greater Synergies

Mumbai: Pharmaceutical major Cipla has completed the amalgamation of its wholly-owned subsidiary Inzpera Health Sciences Limited with itself, following approval from the National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai Bench.

The scheme of amalgamation, approved by an NCLT order dated August 18, 2026, is aimed at consolidating resources and improving operational efficiency. Cipla said the merger will enable better utilisation of resources, greater economies of scale, reduction in overheads and simplified business processes.

The company highlighted deep synergies between the two entities in the manufacturing and marketing of pharmaceutical products. The consolidation is expected to eliminate duplication of efforts, lower compliance costs related to statutory filings and regulatory requirements, and provide unfettered access to cash flows.

According to Cipla, the merger will enhance overall operating parameters and help maximise shareholder value through tighter integration and greater flexibility in operations. As a wholly-owned subsidiary, the amalgamation involves no change in the shareholding pattern of the parent company. The development is part of Cipla's ongoing efforts to rationalise its corporate structure and improve cost efficiency in a competitive pharmaceutical landscape. Industry observers view such internal consolidations as a step towards leaner operations and stronger focus on core business growth.

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.